

104

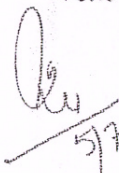
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषदकी दिनांक 28 जून, 1997 को सम्पन्न हुई वर्ष 1997 की तृतीय तथा
परिषद की 166वीं बैठक की कार्यवृत्त

दिनांक 28-6-97 को बैठक प्रारम्भ हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

1. सर्व श्री महेश वत्त शर्मा अध्यक्ष
2. श्री जी०गणेश प्रमुख सचिव,
सार्वजनिक उद्यम विभाग,
उ०प्र० शासन सदस्य
3. डा० अनिल कुमार गुप्ता
आवास आयुक्त सदस्य
4. श्री वीरेश कुमार गुप्ता
विशेष सचिव, आवास,
प्रतिनिधि-सचिव, आवास,
उ०प्र० शासन सदस्य
5. श्री के०के० गोविंदा,
मुख्य अभियन्ता,
प्रतिनिधि-प्रमुख निदेशक,
उ०प्र० जल निगम सदस्य
6. श्री एम०पी०अनेजा
वरिष्ठ नियोजक,
प्रतिनिधि-मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक सदस्य
7. श्री बी०बी०गर्ग,
डिप्टी डाइरेक्टर,
प्रतिनिधि-निदेशक,
सी०बी०आर०आई० रुडकी सदस्य
8. श्री एस०के०वर्मा
मुख्य अभियन्ता
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद सदस्य

विशेष आमन्त्री के रूप में:-

1. श्री ए०के०पचौरी,
मुख्य वास्तुविद नियोजक,
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद सदस्य
2. श्री हमिद मुस्तफा,
वित्त नियन्त्रक,
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद सदस्य


5/7/97

बैठक में विचार विमर्श के उपरान्त सर्व सम्मति से निम्नवत निर्णय लिये गये:-

क्र. सं०	विषय	निर्णय
1	2	3
1.	परिषद की 165वीं बैठक दिनांक 31.3.97 की कार्यवृत्त की पुष्टि।	पुष्टि की गयी।
2.	परिषद की 165वीं बैठक दिनांक 31.3.97 की अनुसूचन आख्या।	अनुमोदित।
3.	योजना संख्या-2 बरेली में स्वयं वित्त पोषित परियोजना-96 बी के अन्तर्गत 53/127 प्रकार के 8 नग फिनिशड भवनों के कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।	अनुमोदित।
4.	योजना संख्या-1 कानपुर में स्वयं वित्त पोषित परियोजना -96 ए के अन्तर्गत 53/127 सेमीफिनिशड, 59/181 सेमीफिनिशड, 76/121 सेमीफिनिशड एवं -//108 फिनिशड प्रकार के क्रमशः 2,2,1 व 1 कुल 6 नग भवनों के निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।	अनुमोदित।
5.	योजना संख्या-1 किच्छा में स्वयं वित्त पोषित परियोजना 96 बी के अन्तर्गत 53/127 प्रकार के 26 फिनिशड भवनों के निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।	अनुमोदित।
6.	इन्दौर नगर विस्तार योजना तखनऊ में स्वयं वित्त पोषित परियोजना 96 ए के अन्तर्गत पूर्व स्वीकृत 63/162 प्रकार के 18 नग सेमीफिनिशड भवनों में से 8 भवनों का फिनिशड भवनों के रूप में निर्मित किये जाने के कार्य की प्रशासनिक एवं	अनुमोदित।

1	2	3
---	---	---

7. योजना संख्या-2 फेज-1 कानपुर में स्थित परिषद के 4 कार्यालयों को योजना के फेज-2 में स्थानान्तरित करने हेतु कार्यालय प्रयोग हेतु प्रस्तावित 68/142 प्रकार के 15 नग सेमीफिनिशड भवनों में आवश्यक फिनिशिंग कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति

अनुमोदित।

8. योजना संख्या-1 कानपुर में किराया पदाति पर आवंटित 43/120 प्रकार के 16 भवनों में अतिरिक्त कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

अनुमोदित।

9. सिकन्दरा योजना, आगरा मथुरा मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली मास्टरप्लान १ एच रोड एवं जेल रोड की मरम्मत का कार्य।

अनुमोदित।

10. बटुपुर योजना संख्या-1 फतेहगढ में स्वयं वित्त पोषित परियोजना 96 ए के अर्न्तगत 63/162 प्रकार के 5 नग सेमीफिनिशड भवनों के कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

अनुमोदित।

11. योजना संख्या -1 मुजफ्फर नगर में स्वयं वित्त पोषित योजना 96ए के अर्न्तगत 64/137 प्रकार के 3 नग सेमीफिनिशड भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

अनुमोदित।

12. हन्स यमुना योजना द्वितीय चरण, आगरा में राईजिंग मेन डालने के कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

अनुमोदित।

[Signature]
9/7/97

1	2	3
13.	इन्दिरा नगर विस्तार योजना लानऊ के सेक्टर-16 में निर्मित 64/137 प्रकार के 20 सेमीफिनिशड भवनों में 1 भवन {भवन सं016/1410}को फिनिशड भवन के रूप में निर्मित करने के कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।	अनुमोदित।।
14.	नेहरू नगर योजना संख्या-1 देहरादून के आंशिक क्षेत्र में बाह्य विद्युतीकरण कार्यों हेतु पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	अनुमोदित।
15.	जागृति विहार योजना संख्या-6 मेरठ में1 नग जीरिंगका निर्माण, 1 नग स्टैण्ड चार्ज फ़र्प की व्यवस्था सहित पुराने फ़िपिंग प्लान आदि के संस्थापन के सम्बन्ध में।-	अनुमोदित।
16.	बसुन्धरा योजना संख्या-3 गाजियाबाद के सेक्टर-2 बी व 2 सी में स्वयं वित्त पोषित परियोजना 96 के अन्तर्गत पूर्व स्वीकृत 62/113 प्रकार के य2 नग फिनिशड एवं 25 नग सेमीफिनिशड भवनों के स्थानपर 3 नग फिनिशड एवं 24 नग सेमीफिनिशड भवनों के निर्माण के प्रस्ताव के फलस्वरूप 1 भवन में फिनिशिंग कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।	अनुमोदित।
17.	योजना संख्या-1 अल्मोडा {सनराइज कालोनी} में क्षतिग्रस्त रिटैनिंग वाल एवं एप्रोच रोड के पुनर्निर्माण के कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	अनुमोदित।

1	2	3
18.	योजना संख्या-2 कानपुर के सेक्टर-5 सी के अवशेष सम्पत्तियों को निस्तारित करने के लिए विद्युतीकरण एवं जलापूर्ति का कार्य तथा अगले 6 माह तक सुरक्षा व्यवस्था की प्रशासनिक स्वीकृति।	अनुमोदित।
19.	परिषद की इन्दु विहार योजना, प्रतापगढ़ की सेवायें नगर पालिका, प्रतापगढ़ हस्तान्तरित किये जानेके सम्बन्ध में?	अनुमोदित।
20.	रिंग रोड योजना संख्या -1 मुजफ्फर नगर में मध्यम आय वर्ग 53/127 प्रकार के फिनिशड भवनों के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में।	अनुमोदित।
21.	उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद के कार्यकलापों की महा मई 1997-98 तक की अध्यावधिक प्रगति रिपोर्ट।	अनुमोदित।
22.	दिल्ली रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं०- 8 प्रथम फेज सहारनपुर की धारा-28 हेतु प्रस्ताव एवं प्रकल्पन।	अनुमोदित।
23.	लोनी रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, गाजियाबाद की धारा-28 हेतु प्रस्ताव एवं प्रकल्पन।	अनुमोदित।
24.	उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की तेलीबाग योजना संख्या-2, लखनऊ की भूमि सीधी बात-चीत के माध्यम से क्रय करने के सम्बन्ध में।	तेलीबाग योजना संख्या-2 लखनऊ की भूमि सीधी बात-चीत के माध्यम से क्रय किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव के बारे में आवास अयुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 23.6.97 को परिषद के कार्य कलापों की समीक्षा माननीय आवास मन्त्री जी की अध्यक्षता में हुई थी। इस समीक्षा बैठक में माननीय अध्यक्ष, आवास एवं विकास परिषद, श्री अतुल कुमार गुप्ता सचिव आवास, श्री वीरेश कुमार विशेष सचिव,

आवास, श्रीएस०के०वर्मा, मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, झरपुर के०पचौरी, मुख्य वास्तुविद् नियोजक, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद एवं श्री बी०के० शोवास्तव, सचिव, आवास एवं विकास परिषद उपस्थित थे। माननीय मन्त्री जी ने इस समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया था कि चूँकि 14 साल से भूमि अर्जन की कार्यवाही लम्बित है और काश्तकारों का शोषण हो रहा है। अतः सीधी बात-चीत के माध्यम से भूमि क्रय करने की कार्यवाही तत्काल की जाय।

आवास आयुक्त ने यह भी अवगत कराया कि माननीय आवास मन्त्री जीके इसी समीक्षा बैठक में यह भी तथ्य आया था कि सीधी बात-चीत के माध्यम से भूमि क्रय करने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या यी०ओ०-185१2१/9-आ-3-93१2१ बी-93 दिनांक 16.8.93 के क्रम में समझौते से भूमि लिए जाने का प्रस्ताव जिलाधिकारी को दिनांक 31.5.97 को प्रेषित किया गया है और तीन अनुस्मारक देने के बाद भी जिलाधिकारी द्वारा अभी भी इसमें कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं की गयी। आवास आयुक्त द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि जिलाधिकारी, परिषद द्वारा तेलीबाग योजना संख्या-2 के 550 बीघे के काश्तकारों से औसतन ₹09=00 प्रति वर्ग फुट की दर से भूमि क्रय किये जानेके प्रस्ताव पर सहमत थे तथा जिलाधिकारी का यह भी मत था कि जो समझौता परिषद द्वारा किया गया है, वह उचित है तथा उपरोक्त वर्णित शासनादेश के क्रम में मण्डलायुक्त को प्रस्ताव अग्रसारित कर देंगे परन्तु जिलाधिकारी द्वारा इस मामले में अब तक कोई कार्यवाही न करने के कारण अग्रिम प्रक्रिया अवरुद्ध है।

आवास आयुक्त द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि परिषद अधिनियम-1965 की धारा-56 के अन्तर्गत परिषद समझौते के माध्यम से भूमि क्रय कर सकती है।

माननीय आवास मन्त्री जी ने दिनांक 27.6.97 को सम्पन्न समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया था कि परिषद समझौते के माध्यम से तत्काल इस भूमि के क्रय करने की कार्यवाही करे। इसी क्रम में परिषद के समक्ष वर्तमान प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर परिषद द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों पर विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि तेलीबाग योजना संख्या-2 के उन 550 बीघे भूमि के सम्बन्ध में औसतन ₹0 9=00 प्रति वर्ग फुट की दर से भूमि क्रय किये जानेके प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति देने हेतु जिलाधिकारी को अन्तिम रूप से अनुस्मारक प्रेषित कर दिया जाय तथा यदि 10 दिनों तक जिलाधिकारी से पत्र प्राप्त नहीं होता है तो मद संख्या-24 पर प्रस्तुत परिषद के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणी के परिशिष्ट में बनायी

1	2	3
25- इन्दिरा नगर द्वितीय विस्तार भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना फैजाबाद सेड लखनऊ की धारा-31१1१ का पुनरीक्षित प्रस्ताव।	समिति तेलीबाग योजना संख्या-2 के काश्तकारों से सीधी बातचीत के माध्यम से प्रस्तावित समझौते के अनुरूप भूमि क्रय करने की नियमानुसार कार्यवाही करे।	अनुमोदित।
26- कमला नगर योजना आगरा स्थित उच्च आय वर्ग भवन संख्या डी-3/7 स्टाफ क्वार्टर आवंटन के सम्बन्ध में।	यदि श्री मोहर सिंह अलीगढ़ योजना संख्या-7 में आवंटित भूखण्ड संख्या-18 का आवंटन स्केछा से नियमानुसार निरस्त करा देते हैं तो कमलानगर योजना आगरा में स्थित स्टाफ क्वार्टर उच्च आय वर्ग भवन संख्या डी-3/7 स्टाफ क्वार्टर से अनारक्षित करते हुए तथा नीलामी से निस्तारण संबंधी नियम को शिथिल करते हुए उन्हें अपंजीकृत क्रेता के रूप में वर्तमान मूल्यांकन के आधार पर नगद क्रय पद्धति पर आवंटित किये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत।	अस्वीकृत।
27- परिषद की विकास नगर योजना लखनऊ के अन्तर्गत श्री महेशचन्द्र व्यास को आवंटित भवन संख्या-4/276 पर लगे दण्ड ब्याज माफी के सम्बन्ध में।	अस्वीकृत।	अस्वीकृत।
28- राजाजीपुरम् योजना लखनऊ के सेक्टर-11 में उपलब्ध डिग्री कालेज की भूमि को राजकीय कन्या महाविद्यालय हेतु उच्च शिक्षा विभाग को आवंटित करने के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की नियमानुसार प्रचलित आवासीय दर की 50 प्रतिशत धनराशि, मिट्टी भरवाई पर होने वाले व्यय ₹0 40.00 लाख कम करते हुए उच्च शिक्षा विभाग से प्राप्त कर ली जाय।	प्रस्ताव इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की नियमानुसार प्रचलित आवासीय दर की 50 प्रतिशत धनराशि, मिट्टी भरवाई पर होने वाले व्यय ₹0 40.00 लाख कम करते हुए उच्च शिक्षा विभाग से प्राप्त कर ली जाय।
29- परिषद की अवधपुरी योजना फैजाबाद में श्री बालेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव को प्रदिष्ट अल्प आय वर्ग भवन संख्या-439 पर दैय ब्याज की माफी के सम्बन्ध में।	अतिरिक्त ब्याज ₹0 2,921.00 माफ करने का प्रस्ताव स्वीकृत।	अतिरिक्त ब्याज ₹0 2,921.00 माफ करने का प्रस्ताव स्वीकृत।

5/11/92

1

2

3

30- परिषद की शास्त्रीनगर योजना संख्या-7, सेक्टर-3 मेरठ में स्थित भूखण्ड संख्या 1383/3 पर निर्माण हेतु अतिरिक्त समय दिये जाने के सम्बन्ध में।

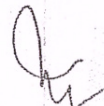
इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की यदि 6 माह के अन्दर भवन निर्माण नहीं किया गया तो भूखण्ड को नियमानुसार परिषद के पक्ष में रिज्यूम करने की कार्यवाही की जायेगी।

31- श्री गिरीश कुमार अवस्थी को परिषद की इन्दरा नगर योजना लखनऊ में आवंटित दुर्बल आय वर्ग भवन संख्या 9/804 के विरुद्ध दण्डव्याज माफ करने के सम्बन्ध में।

3 प्रतिशत दण्ड व्याज ₹0 1,664.35 माफ करने का प्रस्ताव स्वीकृत।

32- फकलव्य बिहार सहकारी आवास समिति लिमिटेड गाजियाबाद की वसुन्धरा योजना गाजियाबाद में भवन आवंटन के सम्बन्ध में।

आवास अयुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 27.6.97 को परिषद के कार्यकलापों की समीक्षा करते समय यह प्रकरण भी मा0 आवास मन्त्री जी, सचिव-आवास, तथा मा0 अध्यक्ष महोदय के आया था। आवास अयुक्त द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि संदर्भित समिति गाजियाबाद में अपने सदस्यों हेतु भूखण्ड चाहती है परन्तु परिषद के दिनांक 28.2.97 को सम्पन्न बैठक में सहकारी आवास समितियों को भूखण्ड आवंटन के सम्बन्ध में नीति निर्धारण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था जिस पर परिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया कि गाजियाबाद में परिषद की एक ही योजना है। जो भूमि नियमानुसार समिति को देय है वह मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार आवंटित की जा चुकी है। कुछ आवास समिति पिछले कुछ वर्षों से भूखण्ड आवंटन हेतु मांग कर रही हैं। वर्तमान में गाजियाबाद में मांग भी अधिक है। इन सभी बिन्दुओं पर विचारोपरान्त परिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया कि गाजियाबाद की आवासीय योजना में सहकारी आवास समितियों को भूमि ग्रुप हाउसिंग हेतु निर्धारित नीति के अन्तर्गत देने पर विचार किया जाय।


5/9/97

....9/-

1

2

3

तदनुसार एकलव्य विहार सहकारी आवास समिति को ग्रुप हाऊसिंग योजना में भूमि का आवंटन किया गया है। सोसाइटी में आवंटन होने पर यह प्रार्थना पत्र दिया कि उन्हें ग्रुप हाऊसिंग के स्थान पर भूखण्ड ही दिया जाय। अतः प्रकरण पुनः परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।


विचारोपरान्त परिषद ने निर्णय लिया कि चूंकि समिति की मांग भूखण्डों की ही है और समिति ग्रुप हाऊसिंग के भूखण्ड लेने के इच्छुक नहीं हैं अतः समिति से वार्ता करके पुनर्विचारोपरान्त प्रकरण परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

33- उ०प्र० जल निगम देहरादून के विरुद्ध अवशेष ब्याज के धनराशि के सम्बन्ध में।

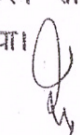
दो सार्वजनिक उपक्रमों के मध्य विवाद उत्पन्न होने के प्रकरण में सार्वजनिक उद्यम विभाग को संदर्भित करके निर्णय प्राप्त किये जाने से संबंधित शासनादेश के अनुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।

34- उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद में भूखण्डों तथा भवनों के पंजीकरण एवं प्रवेशन संबंधी विनियम-1979 की धारा-34 & 38 में आंशिक संशोधन।

सा.वि.
आवास समिति एवं आवास अयुक्त की समिति को आवास को प्रस्तावित अधिकार दिये जाने संबंधी प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।


5/7/97

15. मंगल षण्डेय नगर योजना संख्या-1 मेरठ के विकास कार्यों की पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में। अनुमोदित।
16. योजना संख्या-1 कानपुर में शासन ऋण परियोजना के अन्तर्गत 200 अल्प आय वर्ग § 29/60§ प्रकार के भवनों के निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में। अनुमोदित।
17. नेहरू नगर योजना देहरादून में 53/127 प्रकार के 99 मध्यम आय वर्ग § सेमीफिनिशड§ भवनों की पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में। अनुमोदित।
18. नयी आवास नीति के अन्तर्गत आश्रयहीन परिवारों के लिए ₹ 5=00, ₹ 10=00 व ₹ 15=00 प्रतिदिन की आवाससिद्धि योजना का प्रस्ताव। अनुमोदित।
19. श्री शिव नारायण लाल श्रीवास्तव मोतीनगर लखनऊ को जनता ऋण योजना में स्वीकृत ऋण ₹ 72,000=00 पर लगाये गये दण्ड ब्याज को माफ करने के सम्बन्ध में। अस्वीकृत।
20. श्री रामेन्द्र त्रिपाठी को जनता ऋण योजना में स्वीकृत ऋण ₹ 80,000=00 पर लगाये गये दण्ड ब्याज को माफ किये जाने के सम्बन्ध में। दण्ड ब्याज ₹ 6,701=60 माफ करने का प्रस्ताव स्वीकृत।
21. श्री सुरेश गोपाल महेन्द्र , राजाजीपुरम लखनऊ को जनता ऋण ₹ 1,81,000=00 पर लगाये गये दण्ड ब्याज को माफ किये जाने के सम्बन्ध में। ₹ 5,000=00 दण्ड ब्याज माफी का प्रस्ताव स्वीकृत।
22. खण्डीय स्टेर तत्कालीन विभागीय निर्माण इकाई-चतुर्थलखनऊ से दिनांक 11.1.81 को 100 बोरी सीमेन्ट की अवैध बिक्री के प्रकरण में श्री सी०के० थापर सम्बन्धित अवर अभियन्ता के विरुद्ध शो-काज नोटिस के सम्बन्ध में। स्वीकृत।
23. माननीय आवास एवं नगर विकास मन्त्री एवं आवास सचिव के प्रयोगार्थ दो परस्पर टेलीफोन उपकरण क्रय करने, उनके कनेक्शन लेने तथा उन परकी गयी कालों एवं रन्ट के भुगतान करने तथा आवास आयुक्त, अपर आवास आयुक्त, मुख्य अभियन्ता व मुख्य वास्तुविद विद्यमान नगर नके निजी उपकरणों द्वारा की गयी कालों प्रकरण शासन को संदर्भित करने का निर्णय लिया गया।


5/7/97

1	2	3
---	---	---

एवं रेंट का भुगतान परिषद द्वारा किये जाने की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

- 44. श्री वकील-उर रहमान , अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-33 अलीगढ़ के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 361/पी आर सी/चौ-1-96 दिनांक 31 मई 1996 के अनुरूप कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया-
- 45. स्व० श्री रमेश चन्द्र सहायक अभियन्ताके सुपुत्र श्री प्रशासन्त कुमार को मृतक आश्रित के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति आधार पर परिषद सेवा में नियुक्त करने के सम्बन्ध में। स्वीकृत।
- 46. श्री वी०एन० शर्मा अधिशासी अभियन्ता को चिकित्सा प्रतिपूर्ति दिये जाने के सम्बन्ध में। स्वीकृत
- 47. श्री एन०यू० विलग्रामी का अधीक्षण अभियन्ता के पद पर पदोन्नति के सम्बन्ध में। स्वीकृत।
- 48. परिषद अवर अभियन्ताओं को ₹०. 2200-4000 का प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में। सुसंगत शासनादेश के अनुरूप प्रस्ताव को स्वीकृत किये जाने हेतु प्रकरण प्रशासकीय विभाग को संदर्भित करने के निर्देश दिये गये।
- 49. रिंग रोड योजना संख्या-1 मुजफ्फर नगर में दुर्बल आय वर्ग 18/40 प्रकार के 50 नग भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में। अनुमोदित।
- 50. रिंग रोड योजना संख्या-1 मुजफ्फर नगर में अल्प आय वर्ग 29/60 प्रकार के 30 नग भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में। अनुमोदित।
- 51. श्रीमती पुष्पा बुक्ता के पक्ष में परिषद द्वारा कब्जा प्राप्त 2 विस्वा भूमि पर कराये गये निर्माण को विकास शुल्क लेकर समायोजित करने सम्बन्धी तत्कालीन अध्यक्ष § 40 § द्वारा अनुमोदित निर्णय पर पुनर्विचार करने के सम्बन्ध में। श्रीमती पुष्पा बुक्ता के मामले में पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं है। श्रीमती बिमला बाजपेयी एवं श्री राम दत्त मिश्रा के प्रकरण में परिषद द्वारा पूर्व में लिये गये निर्णय में किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

52. सिकन्दरा योजना आगरा में सीवरा सहकारी आवाससमिति की भूमि के सम्बन्ध में।

अनुमोदित।

53. मझोला भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-48 भाग-28 मुरादाबाद की भूमि सीधी बात-चीत के माध्यम से कय किये जाने के सम्बन्ध में।

अनुमोदित।

54. फिरोजाबाद भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-1 में श्री छदामी लाल जैन (श्री छदामी लाल जैन ट्रस्ट) की अर्जित भूमि खसरा सं० 565 क्षेत्रफल 1-2-0 बीघा में से अवशेष रिक्त भूमि 650 वर्ग मीटर को ट्रस्ट श्री छदामी लाल जैन के नाम आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

असुधार शुल्क लेकर योजना में समायोजित करते हुए आवंटित करने का निर्णय लिया गया।

55. आवास एवं विकास परिषद की तालकटोरा रोड स्ट्रीट योजना, लखनऊ में ग्राम जफरपुर उर्फ रुकुन्दीनपुर, तहसील एवं परगना लखनऊ में खसरा सं० 187 के कुल रक्बा 23-16-0 में से 14-15-10 को विकास/असुधार शुल्क लेकर योजना में समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में।


अनुमोदित।

56. उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा संचालित बोर्ड ऑफ़ पूर्वी योजना, गोरखपुर में स्थित आराजी संख्या 236 रक्बा 0.176 एकड़ भूमि को सदस्य विधान परिषद श्री गणेश शंकर फण्डेय, श्री भीष्म शंकर त्रिपाठी, श्रीमती चन्द्र प्रभा सिंह के पक्ष में समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

अनुमोदित।

57. परिषद की मझोला योजना संख्या-48 भाग-18 मुरादाबाद में समाविष्ट मेसर्स श्री राम स्ट्र बोर्ड मिल्स की 2.90 एकड़ भूमि के सम्बन्ध में।

आवास आयुक्त को अधिकृत किया गया कि वह श्री राम स्ट्र बोर्ड के मालिकों को बुलाकर तथा उनको सुनकर प्रकरण का अन्तिम रूप से निस्तारण करें। निस्तारण करते समय यह भी परीक्षण करवा ले कि श्री राम स्ट्र बोर्ड मिल्स के बगल में राजेन्द्र पलोर मिल की भूमि शासन द्वारा अर्जन मुक्त किये जाने में समानता होने के कारण श्री राम स्ट्र बोर्ड मिल्स की भूमि वयो नहीं अर्जन मुक्त की जा सकती है।


5/7/97

2

3

- मंडोला योजना संख्या-48भाग-28 मुरादाबाद में आवास सचिव एवं आवास आयुक्त को निर्णय समाविष्ट लेबर सहकारी आवास समिति लिमिटेड लेने हेतु अधिकृत किया गया। मुरादाबाद की भूमि के सम्बन्ध में।
- 9- श्री ऊदल सिंह आवंटी अल्प आय वर्ग भवन संख्या 160 राधिका विहार योजना मथुरा के विरुद्ध ब्याज माफी के सम्बन्ध में। स्वीकृत।
- 10- परिषद की राधिका विहार योजना मथुरा में श्री किशनचन्द्र को आवंटित मध्यम आय वर्ग भवन संख्या 588 के विरुद्ध देय ब्याज माफ करने के संबंध में। स्वीकृत।
- 61- सेण्ट्रल एकाडमी एजुकेशन सोसाइटी को इन्दिरा नगर योजना लखनऊ के सेक्टर-9 में शैक्षिक प्रयोग हेतु भूमि आवंटन के सम्बन्ध में। स्वीकृत।
- 62- परिषद की विकास नगर योजना लखनऊ में श्रीमती अफसर जहाँ को प्रविष्ट मध्यम आय वर्ग भवन संख्या 5/65 पर देय दण्ड ब्याज माफ करने के सम्बन्ध में। अतिरिक्त ब्याज ₹0 3,424.25 माफ करने का प्रस्ताव स्वीकृत।
- 63- राजाजीपुरम् योजना लखनऊ में अल्प आय वर्ग भवन संख्या 221 के विरुद्ध दण्ड ब्याज माफ करने के सम्बन्ध में। अस्वीकृत।
- 64- श्री वी0एन0 शर्मा, अधिशासी अभियन्ता, द्वितीय वृत्त मेरठ को स्टाफ क्वार्टर मध्यम आय वर्ग भवन संख्या-सी-69 आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में। स्वीकृत।
- 7- इन्दिरा नगर विस्तार योजना 8द्वितीय8 लखनऊ के अर्न्तगत दीन दयाल पुस्त्र में आश्रयहीन परिवारों के लिये टाइप-बी815/258 प्रकर के 1000 भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति करने के संबंध में। स्वीकृत।
- 8 स्वयं वित्त पोषित योजना एवं डिजिटल कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के प्रस्ताव आवास आयुक्त स्तर से स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में। डिजिटल कार्यों के संबंध में शासन/संबंधित संस्थाओं द्वारा निर्गत प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति को आधार मानकर निर्माण/विकास कार्य सम्पन्न किये जायें। परिषद के समक्ष डिजिटल कार्यों की सूची बनाकर अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जाय।

5/11/17

1

2

3

67. वेतियाहाता पूर्वी योजना गोरखपुर में स्वयं वित्त पोषित योजनाके अन्तर्गत आवंटित भवन संख्या 13 के विरुद्ध दण्ड ब्याज के सम्बन्ध में।

दण्ड ब्याज ₹0 4,400=00 तथा विविध शुल्क समय सीमा में जमा न करने के कारण आरोपित ₹0 7466=00 कुल ₹0 11,866=00को माफ करने का प्रस्ताव स्वीकृत।

68. प्लेक्स बिला योजना , नैनीताल में स्वयं वित्त पोषित योजना 94ए के सम्बन्ध में ।

स्वयं वित्त पोषित योजना 94 ए के अन्तर्गत पंजीकरण को निरस्त करते हुए पंजीकरण धनराशि वापस करने का प्रस्ताव स्वीकृत।

69. परिषद के 21 कर्मचारियों को विशेष परिस्थितियों में आउट ऑफ टर्न" भवन अग्रिम स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव स्वीकृत। भविष्य में सार्वजनिक उद्यमों के सेवकों को भवन निर्माण के लिए ऋण की सुविधा उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्या 428/चौ-1-उ0वे0रि0/88-41/85 दिनांक 31 जुलाई 1989 के अनुसार कार्यवाही करने पर विचार करने के निर्देश दिये गये।

70. परिषद में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को प्रोन्नति वेतन मान स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रशासकीय विभाग को संदर्भित करने के निर्देश दिये गये।

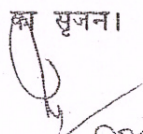
71. परिषद के कार्य क्षेत्र एवं बड़े हुए कार्य कलाओं पर प्रभावी नियन्त्रण एवं सुनियोजित क्रियान्वयन हेतु क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता स्तर-2 ,अधीक्षण अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता तथा सहायक अभियन्ताओं के पदों को सृजन व उन पर प्रोन्नति।

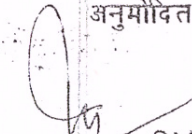
सम्पूर्ण प्रकरण पर संहत प्रस्ताव बनाकर तथा इस प्रस्ताव में वित्त से सम्बन्धित अधिकारों के प्रस्ताव को सम्मिलित करते हुए प्रस्ताव शासन को प्रेषित करने के निर्देश दिये गये।

72. वाराणसी जोन का सृजन।

अनुमोदित ।

...15/-


07/1/97


07/1/97

1	2	3
---	---	---

73. अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य मद:-

§ 1 § 30प्र0 आवास एवं विकास परिषद की वसुन्धरा न्यायालय में प्रकरण के लम्बित रहने के कारण विधि परामर्श लेकर तदनुसार अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
 2 योजना गाजियाबाद में समाविष्ट ग्राम प्रहलादगढ़ी एवं कानपुर में माननीय न्यायालय से प्रभावित 16-16-2-0 बीघी भूमि के सम्बन्ध में।

§ 2 § परिषद द्वारा संचालित योजनाओं में व्यवसायिक सम्पत्ति व निरस्तीकरण के पश्चात पुनर्जीवन के संबंध में। स्वीकृत

§ 3 § परिषद के विधि परामर्शदाता को परिषद बैठकों में विशेष आमन्त्री के रूप में भाग लेने के संबंध में। स्वीकृत

पुनर का गया
 अ. ए. ए. ए. ए.
 31.12.21

प्रमग्न सचिव, आवास की अध्यक्षता में गठित उप समिति की बैठक दिनांक ३.३.९७ को कार्यवृत्त दिनांक ३.३.९७ को उप समिति की बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए-

- १- श्री ए०पी० सिंह
प्रमुख सचिव
उ०प्र० शासन, आवास विभाग। अध्यक्ष
- २- श्री शेखर अग्रवाल,
सचिव,
उ०प्र० शासन,
वित्त विभाग। सदस्य
- ३- श्रीमती सुरजीत कौर सन्धु
आवास आयुक्त सदस्य

क्र० सं०	उप समिति द्वारा विचार करने वाले मदों की संख्या	निर्णय
१-	२८	निर्देशित किये गये कि इसका विस्तृत परीक्षण करके पुनः इसे कमेटी के समक्ष रखा जाय।
२-	२९	निर्देशित किये गये कि इसका विस्तृत परीक्षण करके इसको पुनः कमेटी के समक्ष रखा जाय।
३-	३३	विचारोपरान्त दण्ड ब्याज माफ करने का निर्णय लिया गया। देय मूल धनराशि पर साधारण ब्याज जल निगम विभाग से वसूल कर लिया जाय।
४-	३४	विचारोपरान्त प्रस्ताव को स्वीकृत किये गये।
५-	६०	प्रस्ताव पर विचार किये गये। विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि डानवास्वै स्कूल को १.४८ एकड़ भूमि ५० प्रतिशत छूट की दर से परिवर्द्ध नियमानुसार जो स्कूल के लिए अनुमन्य है, के अनुसार छूट देते हुए भूमि स्कूल के लिए छोड़ दी जाय।
६-	६३	विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि इसमें शासनादेश जो हुए हैं उसी के अनुसार कार्यवाही की जाय।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

१	२	३
७-	६४	स्वीकृत किया गया।
८-	६५	निर्णय लिया गया कि यह ज्ञात कर लिया जाय कि सार्वजनिक ब्यूरो ने उसमें क्या कार्यवाही की है इसकी जानकारी प्राप्त कर ली जाय तब उसके बाद परिषद के समक्ष रखा जाय।
९-	६६	विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।
१०-	६७	विचारोपरान्त स्वीकृत किया गया।
११-	६८	विचारोपरान्त स्वीकृत किया गया।
१२-	६९	विचारोपरान्त अस्वीकृत किया गया।
१३-	७०	प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया कि शासनादेश के द्वारा इसमें स्पष्ट आदेश दिये गये हैं। अतः इस भूमि का विकास शुल्क लेकर छोड़ना उचित होगा। अतः वर्तमान दर विकास शुल्क लेकर छोड़ दी जाय।